Name: Razia

Name of Supervisor: Dr.Farha Naaz

Department: Political Science

Jamia Millia Islamia

New Delhi-110025

National Minority Commission-Muslims ka Vikas

Abstarct

इस प्रस्तावित शोध विषय ''नेशनल माइनोरिटी कमिशन: मुस्लिम्स का विकास'' में मुसलमानों के पिछड़ेपन को दूर करने और उनके विकास के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई है। मुसलमान अल्पसंख्यकों की संख्या भारत में अन्य अल्पसंख्यकों की तुलना में अधिक है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का मुख्य कार्य अल्पसंख्यकों के सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन की समीक्षा करना, उनके उत्थान के लिए प्रयास करना एवं सरकार को उचित सलाह देना है। इस प्रस्तावित शोध विषय में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना के उद्देश्य, अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा गठित किए गए विभिन्न आयोगों के कार्य एवं उनके योगदान और उनकी विफलताओं की समीक्षा की गई है। प्रस्तावित शोध विषय में अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में दिए गए प्रावधान और उनके वास्तविक क्रियान्वयन पर भी सूक्ष्म दृष्टिपात किया गया है। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणराज्य में आज भी धार्मिक, जातीय और भाषाई आधार पर भेदभाव किया जाता है, जिसके कारण उनका सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास नहीं हो पाता और वे पिछड़ जाते हैं। उपरोक्त सन्दर्भ में भी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की भूमिका को बताने का प्रयास किया गया है। आज भारत में मुसलमानों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे–लोक सेवाओं एवं अन्य सेवाओं में अल्प–प्रतिनिधित्व की समस्या, धर्म पर आधारित भेदभाव की समस्या एवं वक्फ़ संपत्ति की समस्या इत्यादि। इन सभी समस्याओं के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा गठित कुछ समितियों की रिपोर्ट, उनके द्वारा मुसलमानों के सन्दर्भ में की गई विशेष टिप्पणियॉ, संसद की स्थायी समितियों द्वारा दी गई रिपोर्ट एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा समय–समय पर किए गए विकास कार्यों का अध्ययन किया गया है।

प्रस्तावित शोध की परिकल्पना यह है कि मुसलमानों के विकास में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की भूमिका बहुत कम रही है, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पास

पर्याप्त शक्ति एवं अधिकार नहीं हैं। इसके अलावा मुसलमानों के पिछड़ेपन का अन्य मुख्य कारण यह भी है कि मुसलमान जन–प्रतिनिधियों के द्वारा आम जनता तक इनकी गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। यद्वपि मुसलमान बहुत बड़ी मात्रा में अन्य अल्पसंख्यक वर्गों की तुलना में अशिक्षित और अत्यधिक पिछड़े हुए हैं और उन्हें सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में भी सूचना नहीं होती, जिसके परिणामस्वरूप मुसलमान सरकार द्वारा प्रदान किए गए कार्यक्रमों को ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जन–प्रतिनिधियों द्वारा मुसलमानों के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक सभी सरकारी विकास कार्यक्रमों का प्रचार करना चाहिए और इन विकास कार्यक्रमों को लागू कराने के लिए सरकार पर दबाव भी रखना चाहिए। प्रस्तावित शोध के उद्देश्य में वर्तमान समय में मुसलमानों के पिछड़ेपन, सरकार द्वारा उनके उत्थान के लिए प्रदान किए गए अनुदान का अध्ययन, 15–सूत्री कार्यक्रम के सैद्धांतिक एवं वास्तविक पक्षों पर ध्यान देना, कुछ विशेष योजनायें जैसे–स्वरोजगार योजना, महिला विकास योजना, उर्दू भाषा संरक्षण व मदरसा आधुनिकरण एवं इसी प्रकार के अन्य कई प्रस्तावित कार्यक्रम जो मुसलमानों के विकास के लिए उल्लेखित किये गए हैं उनका अध्ययन किया गया है। उपरोक्त अध्ययन हेतु शोधकार्य ऐतिहासिक एवं समीक्षात्मक दोनों प्रकार की विधियों के आधार पर किया गया है और इस शोधकार्य में साक्षात्कार तकनीकी का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा शोधकार्य में अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित विभिन्न समिति व आयोग की रिपोर्ट, संवैधनिक प्रावधान, स्कीम एवं नीतियों का अध्ययन भी किया गया है।

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर देश में मुसलमानों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्न सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं–

–भारत में मुसलमानों की स्थिति को अधिक बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है, कि भारत सरकार को मुसलमानों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए एवं उन्हें विकास के सभी अवसर प्रदान किए जाने चाहिऐं, ताकि वे देश की मुख्यधारा में सम्मिलित हो सकें और समाज के अन्य समुदायों के समान ही सभी सुरक्षा उपायों का भरपूर लाभ उठा सकें।

–अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए प्रत्येक क्षेत्र एवं राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए एक संस्था खोली जानी चाहिए।

–मुसलमान युवकों के प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की तकनीकी एवं पोलिटेक्निक संस्थाऐं स्थापित करनी चाहिऐं तथा उन्हें भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक संस्थानों में भी लाभ उठाना चाहिए।

–भारतीय मुसलमानों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आवश्यक है, कि भारतीय मुसलमानों की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को सुधारा जाए।

–सभी राजनीतिक क्षेत्रों में जैसे– विधानसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा में मुसलमानों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ताकि उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके।

–मुसलमानों को अपनी स्थिति सुधारने के लिए अन्य समुदायों विशेष रूप से हिन्दू समुदाय से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए।

–भारत में मुसलमानों के विकास के लिए एक आवश्यक तत्व है– अधिक से अधिक NGOs की स्थापना करना, जिसका सम्पूर्ण भारत में पूर्ण अभाव है।

****